www.tamsasanket.com
वर्षः 06 || अंक 18 || लखनऊ
शनिवार
18 अप्रैल 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 05:40
सूर्यास्तः 06:32
अधिकतमः 41°00
न्यूनतमः 26°00

पेज 03

विशेष समाचार
- मौसम विभाग की आंख मिचोली... >> पेज 02
- एटीएम तोड़ने वाला निकला कंपनी... >>पेज 04
- दीपिका के सपोर्ट में आईं कंगना...

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 54 वोट से गिरा

पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े, मोदी सरकार पहली बार बिल पास कराने में नाकाम

तमसा संकेत, एजेंसी

महिला आरक्षण बिल से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में 528 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी। 528 का दो तिहाई 352 होता है। इस तरह बहुमत नहीं मिलने से ये बिल पास 54 वोट से गिर गया। 11 साल के शासन में यह पहला मौका जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। इससे पहले अमित शाह ने एक घंटा स्पीच दी थी। कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। इन संशोधित बिलों पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई। कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखें, इनमें 56 महिला सांसद थीं। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है। लोकसभा में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सीटों के परिसीमन से जुड़े तीन संशोधित बिलों पर आज लोकसभा में दूसरे दिन चर्चा जारी है। बिलों पर आज ही वोटिंग होगी। 70 सालों में कांग्रेस ने कभी इन राज्यों में महिलाओं को मौका नहीं दिया। आज भी दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम भाजपा ने बनाया। इस देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मू बनीं। आज 14 लाख महिलाए जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायत में काम कर चुकी है शाह ने कहा- नेहरू, इंदिरा और राजीव ने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में दिया। क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है। 15-20 बार चुनाव हार गए तो ओबीसी का हीतैशी बन रहे हैं। अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को पीएम बनाया। किसी ओबीसी को पीएम नहीं बनाया। मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 40 फीसदी हैं। मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को मान्यता दी।

>> (शेष पेज 04 पर)

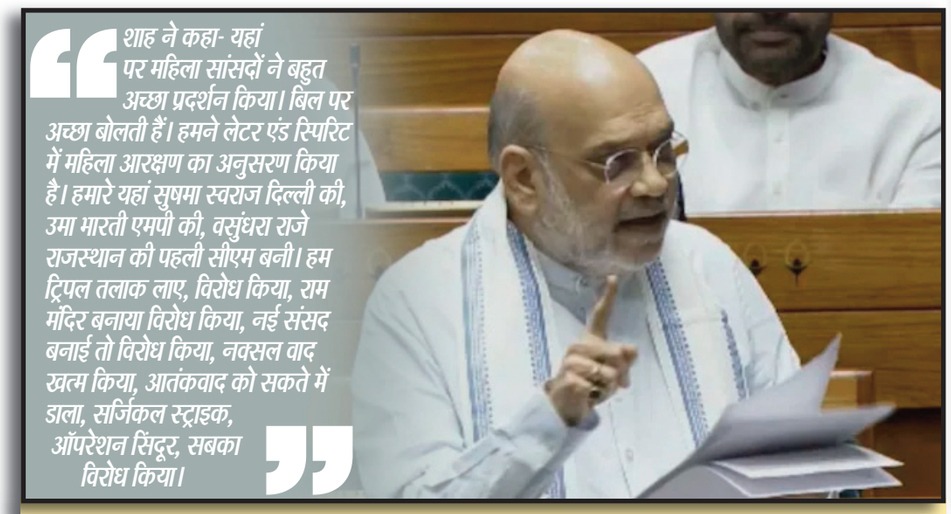

शाह ने कहा- यहां पर महिला सांसदों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल पर अच्छा बोलती हैं। हमने लेटर एंड स्पिरिट में महिला आरक्षण का अनुसरण किया है। हमारे यहां सुषमा स्वराज दिल्ली की, उमा भारती एमपी की, वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली सीएम बनी। हम ट्रिपल तलाक लाए, विरोध किया, राम मंदिर बनाया विरोध किया, नई संसद बनाई तो विरोध किया, नक्सल वाद खत्म किया, आतंकवाद को सकते में डाला, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, सबका विरोध किया।

शाह बोले- मैं 50 प्रतिशत सीटे बढ़ाने वाला संशोधन बिल लाने को तैयार

वेणुगोपाल ने दो सवाल किए- एक तो 50 प्रतिशत सीटे बढ़ाने कि लए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हैं।

- **अमित शाह:** हां मैं तैयार हूं, एक घंटे सदन बंद कर दीजिए। मैं अमेंडमेंट ला दूंगा। बोलिए तैयार हैं। परिसीमन 2026 की जनगणना का सवाल है तो मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा।
- **स्पीकर ओम बिरलाः** कई बार सदन में फैसले हो जाते हैं। यहीं फैसला कर लो।
- **अखिलेश यादवः** अभी तक 11 साल का अनुभव है, अगर भाजपा लिखकर दे देंगे कि हम महिला pm बनाएंगे तो भी मैं इनपर भरोसा नहीं करूंगा।

शाह बोले- ट्रिपल तलाक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, विपक्ष ने विरोध किया

शाह ने कहा- हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि महिलाओं को प्रस्थापित करने के लिए, उनकी हिस्सेदारी देने के लिए जिसका भी सामना करना पड़े। हम करेंगे, लड़ेंगे और आरक्षण देकर रहेंगे। एक पत्रकार का फोन आया कि विरोध का तो कारण ही नहीं है। मैंने कहा कि देखों सिर्फ महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं हो रहा है।

इन तीन बिलों पर लोकसभा में चर्चा

- **संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026:** लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है। राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं।
- **परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2026:** परिसीमन के लिए 'जनसंख्या' की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए।
- **केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026:** यह विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सकें।

शाह बोले- विपक्ष बिना सोचे-समझे बस विरोध कर रहे हैं

शाह ने कहा- विपक्ष ने अच्छा बुरा सोचे बिना मोदी जी जो करे रहे हैं, उसका विरोध करने का ठान लिया है। देश की माताओं बहनों के लिए आरक्षण आ रहा है तो लग रहा था विरोध नहीं होगा। लेकिन हो रहा है। मैं अभी बताया कि 2023 में सर्वसम्मति से ये बिल पारित हुआ लेकिन आज कांग्रेस पीछे हट रही है। इसके दो ही कारण हैं- क्योंकि बिल मोदी जी ला रहे हैं और क्रेडिट उन्हें मिलेगा। मोदी जी ने उन्हें एड देकर क्रेडिट देने का कह दिया फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। हमारे नेता ने कहा कि अंतरआत्मा की आवाज से वोट करिए। अंतरआत्मा की आवाज का नारा इंदिरा जी का है।

पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज

एससी ने कहा- असम कोर्ट जाएं, खेड़ा बोले- क्या मैं कोई अपराधी हूं?

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि वे अपनी याचिका असम की अदालत में दाखिल करें। पवन खेड़ा की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। उन्होंने कहा- असम की अदालतें बंद हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए। क्या खेड़ा कोई अपराधी हूं, जो मुझे इतनी राहत भी नहीं मिल सकती? जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने यह मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने उन्हें गलत डाक्यूमेंट देने के लिए फटकार भी लगाई। यह मामला असम सीएम हिमंता बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा को लेकर दिए गए आरोपों से जुड़ा है। खेड़ा ने 5 अप्रैल को आरोप लगाया था कि उनके पास एक से ज्यादा पासपोर्ट और विदेश में संपत्तियां हैं, जिनका जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रांजिट जमानत शुक्रवार को खत्म हो रही है, इसलिए इसे मंगलवार तक बढ़ा दिया जाए ताकि वे सोमवार को असम में याचिका दाखिल कर सकें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि खेड़ा ने सीधे असम की अदालत का रुख क्यों नहीं किया और पहले तेलंगाना हाईकोर्ट क्यों गए।

टीएमसी सांसद बोलीं- चोली के पीछे क्या है चुनरी के नीचे क्या है

टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि देश को सरकार बताना चाहती है कि विपक्ष महिलाओं के विरोध में है। ये सच नहीं है। हमने आरक्षण बिल 2023 में स्वीकार कर लिया था। हिंदी का गाना याद आ रहा है कि चोली के पीछे क्या है चुनरी के नीचे क्या है। चोली के पीछे यानी आरक्षण बिल के पीछे परिसीमन की क्या है इसे क्यों जोड़ दिया गया है। 56 इंच के सीने की बात करने वालों को औरत के पीछे छिपना पड़ रहा है इस बिल के अंदर।

सांसद रवि किशन बोले- मेरा प्रचार पत्नी करती हैं, मैं उनके पैर छूता

भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा- मेरा प्रचार भी मेरी पत्नी करती हैं। मेरा एक डेढ़ लाख वोट पत्नी लाती हैं। मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं। क्यों न छुएं उसने मेरी गरीबी और स्ट्रगल में साथ दिया। हालांकि वो छूने नहीं देती मैं उनके सोते हुए पैर छू लेता हूं। यहां लोग अपने गार्डन की कहानी सुनाकर चले गए। पीएम का अपमान कर गए।

शाह बोले- 2024 में चुनाव के चलते कांग्रेस विरोध नहीं कर पाई

शाह ने कहा- 1992 में नरसिम्हा राव 72 और 73 का संविधान संशोधन लेकर आए और पंचायत में महिलाओं को 33 फीसदी देने का आरक्षण का काम किया। वे कांग्रेस के पीएम थे लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कभी अपना पीएम नहीं माना।

बीजेपी ने कभी इस बिल का विरोध नहीं किया।

कांग्रेस सरकार में उन्हें समर्थन देने वाली पार्टियों ने बिल का विरोध किया। 2023 में मोदी जी विधेयक लाए। उनको पता था 2024 में चुनाव है कांग्रेस विरोध नहीं कर पाएगी।

तब नारी शक्ति वंदन एक्ट पारित हुआ। लेकिन लागू कराने में आए तो फिर से विरोध कर रहे हैं, देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेंगी।

शाह ने कहा- मैं सरकार की, संविधान की और भाजपा की पॉलिसी साफ करना चाहता हूं। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता। संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण की मान्यता नहीं है। इंडी अलायंस ने तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम आरक्षण की मांग खड़ी करना चाहते हैं। हमारी सरकार की नीति साफ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण न आज देंगे न किसी को देने देंगे। ओबीसी आरक्षण पर- देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोध पार्टी है तो कांग्रेस है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी, दोनों को कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया। 1957 में काकासाहेब समिति के सुझाव आए, कांग्रेस ने सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

सबरीमाला केस में 5वें दिन की सुनवाई

याचिकाकर्ता बोला- आस्था और विश्वास समय के साथ बदलते हैं

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट राजीव धवन ने कोर्ट से कहा कि आस्था या विश्वास समय के साथ हमेशा बदलते रहते हैं। यह बदलाव सिर्फ किसी कानून के बन जाने से नहीं आता; बल्कि यह बदलाव तो लोगों के बीच से ही उभरकर आता है। इससे पहले 9 जजों की बेंच ने 15 अप्रैल की सुनवाई में कहा था कि करोड़ों लोगों की आस्था को गलत ठहराना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। साथ ही यह भी कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। वहीं मंदिर प्रशासन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) ने कहा कि सबरीमाला कोई खिलौने की दुकान या रेस्टोरेंट का मामला नहीं है। यहां के देवता ब्रह्मचारी हैं। भारत में अयप्पा के लगभग 1,000 मंदिर हैं। अगर महिलाओं को दर्शन करना है, तो वहां जाएं।

फास्ट न्यूज

संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढहाई गई

संभल। संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार शुक्रवार दोपहर डेढ़ बजे गिरा दी गई। अब बुलडोजर मस्जिद के बाकी हिस्सों को तोड़ रहा है। इससे पहले, सुबह साढ़े 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मस्जिद के बाहर की पांच दुकानों को तोड़ा गया। मस्जिद की मीनार तोड़ने के लिए प्रशासन ने दो हाइड्रा मशीनें बुलाईं। एक मजदूर मीनार पर चढ़कर रस्सी को बांधा, फिर उसके दूसरे सिरे को दोनों हाइड्रा मशीनों से बांधा।

देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा : हिमंता

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा- हर जनगणना में मुस्लिम आबादी 4-5% बढ़ी है। असम में भी यही हो रहा है। मैं बंगाल के लोगों से अपील करता हूं कि देश को बचाना आपके हाथों में है। नहीं तो देश बांग्लादेशी मुसलमानों का अड्डा बन जाएगा। वहीं, दमदम की सभी में सीएम ममता बनर्जी ने कहा- जब कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे, तब आपके घरों पर भी ये छापे पड़ेंगे। आप बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कूच बिहार की सभा में उन्होंने कहा- हमारे पार्टी कार्यालयों, कैंडिडेट के घरों तक पर छापेमारी हो रही है। लेकिन, चाहे कितनी भी साजिश रच लें, भाजपा को हार का सामना करना ही होगा।

एमपी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की डकैती

सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिनदहाड़े बैंक डकैती का मामला सामने आया है। यहां बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार दोपहर 5 हथियारबंद बदमाश घुसे। फायरिंग कर करीब 9-10 किलो सोना और 20 लाख कैश लेकर भाग गए। सोने की कीमत करीब 15 करोड़ आंकी गई है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की है। जानकारी के मुताबिक, लूटा गया सोना ग्राहकों का था।

यूपी पुलिस का 'हाई-टेक' अवतार

500 क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार कर रही योगी सरकार, वैज्ञानिक जांच से अपराधियों पर कसेगा शिकंजा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में योगी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। 'जीरो टॉलरेंस' नीति को जमीन पर उतारते हुए अब यूपी पुलिस पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक जांच के सहारे अपराधियों तक पहुंचेगी। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) में 500 क्राइम सीन एक्सपर्ट तैयार करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है, जिसमें अब तक 300 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। यह पहल सिर्फ संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम मानी जा रही है। प्रशिक्षित अधिकारी अब फील्ड में जाकर जांच को अधिक सटीक और प्रभावी बनाएंगे, जिससे अपराधियों के बच निकलने की गुंजाइश बेहद कम हो जाएगी। इस योजना की खास बात इसकी 'मल्टीप्लायर रणनीति' है। UPSIFS से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी अपने-अपने जिलों और कमिश्नरेट में 'मास्टर ट्रेनर' की भूमिका निभाएंगे। ये अधिकारी कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मियों को आधुनिक जांच तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे। वर्कशॉप और ट्रेनिंग सत्रों के जरिए साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल साक्ष्य संरक्षण और क्राइम सीन मैनेजमेंट जैसी अहम तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इससे पूरे प्रदेश में फॉरेंसिक पुलिसिंग की एक मजबूत और एकीकृत प्रणाली विकसित होगी।

>> (शेष पेज 04 पर)

वैज्ञानिक जांच पर जोर, हर सबूत होगा अहम

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को सिखाया जा रहा है कि घटनास्थल पर पहुंचते ही डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों को कैसे सुरक्षित किया जाए। साथ ही साइबर ट्रैकिंग, सैंपल कलेक्शन और एविडेंस प्रिजर्वेशन की आधुनिक विधियों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी छोटा से छोटा साक्ष्य नजरअंदाज न हो और उसे वैज्ञानिक तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके। इससे न केवल जांच प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि अपराधियों को सजा दिलाने में भी सफलता दर बढ़ेगी।

लेबनान में सीजफायर के बाद फैसला, ट्रम्प बोले- शुक्रिया, लेकिन ईरान की नाकाबंदी जारी रहेगी

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोला, कमर्शियल जहाज गुजर सकेंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन। ईरान ने सीजफायर के दौरान होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खोल दिया है। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने X पर पोस्ट कर बताया कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। यह फैसला लेबनान में सीजफायर के बाद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जहाज एक सुरक्षित रास्ते से गुजरेंगे, जिसे ईरान के पोर्ट्स और मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से तय कर रखा है, ताकि सफर के दौरान कोई खतरा न हो। अराघची ने कहा कि इस दौरान जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान को शुक्रिया कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है लेकिन ईरान पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी और यह सिर्फ ईरान पर लागू होगी। ट्रम्प ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड (संवर्धित) यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से यह भी कहा कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह डील हो जाती है।

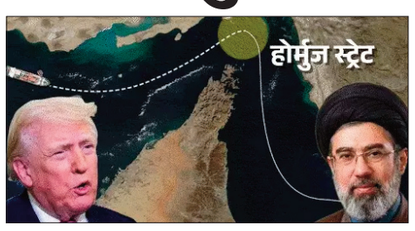

> ट्रम्प ने कहा है कि इजराइल अब लेबनान पर बमबारी नहीं करेगा और इसे अमेरिका ने रोक दिया है।

परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब ईरान

यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है, जिससे परमाणु ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और परमाणु बम भी। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसे कितना एनरिच यानी शुद्ध किया गया है। प्राकृतिक यूरेनियम में काम का हिस्सा बहुत कम होता है, इसलिए उसे मशीनों (सेंट्रीफ्यूज) के जरिए स्टेप बाय स्टेप शुद्ध किया जाता है। इसी प्रक्रिया को 'यूरेनियम एनरिचमेंट' कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी IAEA की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास कुल मिलाकर करीब 5 से 6 टन के बीच एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। हालांकि, यह इतना एनरिच्ड नहीं है कि इससे परमाणु हथियार बन सकें।

राहुल के खिलाफ एफआई दर्ज करने का आदेश

उन पर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- सीबीआई जांच करे

कार्यवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा, FIR दर्ज करके मामले को CBI को ट्रांसफर किया जाए। CBI इसकी जांच करेगी। कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। उन्होंने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था। 28 जनवरी, 2026 को MP-MLA कोर्ट ने विग्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था- 'मामले में हाईकोर्ट- सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से नागरिकता (सिटीजनशिप) के संबंध में कोई नया या ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।' हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को लगाए गए आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं थी। सुनवाई के दौरान जज सुभाष विद्यार्थी ने गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन को निर्देश दिए थे कि मामले से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज पेश करें। मंत्रालय ने केस से जुड़ी सभी फाइलें हाईकोर्ट में पेश कीं। विग्नेश शिशिर का दावा है कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी यूनाइटेड किंगडम में मतदाता रहे हैं। वहां चुनावों में भागीदारी से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

राहुल के खिलाफ यूपी में 3 केस

- राहुल के खिलाफ मानहानि का एक केस सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहा है। यह मामला 2018 का है। जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का आरोप लगाया था। 20 फरवरी, 2024 को कोर्ट ने राहुल को 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी थी। शुक्रवार, 17 अप्रैल को कोर्ट ने वादी विजय मिश्रा को बार-बार स्थगन आदेश लेने पर कड़ी चेतावनी दी है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
- लखनऊ की एक अदालत में राहुल पर वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान के कारण भी मामला दर्ज है। इस मामले में राहुल गांधी को 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
- हाथरस की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि केस चल रहा है। बूलगढ़ी गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने यह परिवाद दाखिल किया है। आरोप है कि अदालत से दोषमुक्त हुए युवकों को गैंगरेप का आरोपी बताया।

याचिका दायर करने वाले विग्नेश शिशिर ने कर्नाटक भाजपा के कार्यकर्ता हैं। (फाइल फोटो)

2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिका खारिज कर दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राहुल की भारतीय नागरिकता से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी। उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि अगर कोई कंपनी किसी फॉर्म में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक के तौर मेंशन करती है, तो क्या ऐसा कर देने से ही वे ब्रिटिश नागरिक हो गए। सीजेआई गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था- 'हम यह याचिका खारिज करते हैं। इसमें कोई आधार नहीं है। 'याचिका में कहा गया था।

भाजपा नेता की हत्या में कर्नाटक कांग्रेस एमएलए को उम्रकैद

2016 के केस में विनय कुलकर्णी समेत 17 को सजा, सीबीआई ने जांच की थी

सजा

तमसा संकेत, एजेंसी

बेंगलुरु। कर्नाटक के भाजपा नेता योगेश गौड़ा गौदार हत्याकांड में बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी समेत 17 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कर्नाटक के धारवाड़ में 15 जून 2016 को बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की उनके जिम में हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने जांच की, लेकिन राजनीतिक दबाव और आरोपों के चलते 2019 में मामला CBI को सौंप दिया गया था। कोर्ट ने 15 अप्रैल को कांग्रेस विधायक और 16 अन्य लोगों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था। स्पेशल जज संतोष गजानन भट ने कहा कि सभी दोषियों ने मिलकर हत्या की आपराधिक साजिश रची थी। मामले में कांग्रेस विधायक को मुख्य साजिशकर्ता माना गया। कोर्ट के फैसले के बाद कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता पर भी असर पड़ सकता है।

सीबीआई ने 5 नवंबर 2020 को विनय कुलकर्णी को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था।

सम्पादकीय

वेदांता हादसा, वही पुराने सवाल

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए बड़े हादसे ने बिहार से बंगाल तक कई परिवारों पर बड़ा दुख बरपाया है। 14 अप्रैल की दोपहर में प्लांट की बॉयलर यूनिट के पास अचानक एक बड़ा धमाका हुआ, जिसने पल भर में कई जिंदगियों को लील लिया। घोषित तौर पर इस हादसे में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है और कम से कम 36 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। लेकिन हताहतों का असली आंकड़ा क्या है, यह दावे से कौन कह सकता है, क्योंकि सात सौ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान वाला बॉयलर जब फटा तो उस वक्त बड़ी संख्या में श्रमिक पेंटिंग और तकनीकी काम कर रहे थे। जिनमें से कुछ वहीं मारे गए, कुछ अस्पतालों में इलाज के दौरान मरे, और कुछ तो अंतिम संस्कार से पहले ही राख में तब्दील हो गए। मुर्दाघर के बाहर अपने परिजनों की शिनाख्त में लोग भटकते रहे, क्योंकि शवों की पहचान भी मुश्किल हो गई थी। कुछ श्रमिकों के परिजनों का दावा है कि प्लांट के भीतर काम करने गए कई लोग अब भी लापता हैं। बहरहाल इस हादसे के बाद जैसा कि रिवाज है, कंपनी ने, राज्य सरकार ने और इस बार तो केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुख जताते हुए लिखा, 'छत्तीसगढ़ के सिंघीतराई प्लांट में हुए दुखद हादसे से गहरा दुख हुआ है। इस हादसे से प्रभावित हर व्यक्ति मेरा परिवार है। आपके आंसू मेरे हैं, आपका दर्द मेरा है। हमारा पूरा सहयोग, हर तरह से आपके साथ है।' इसमें कोई दो राय नहीं कि कंपनी के मालिक को इस तरह के हादसे पर दुख है, लेकिन हताहतों के परिजनों पर जो बीती है, जो आंसू उनकी आंखों में हैं, वो मालिकान के कैसे हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद ऐसे हादसे होने की नौबत ही नहीं आती। फिलहाल यह पता नहीं है कि बॉयलर किस वजह से फटा, इसलिए किसी पर सीधे दोषारोपण नहीं हो सकता। लेकिन अक्सर ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाओं में यही देखा जाता है कि जरा सी लागत बचाने के फेर में रख-रखाव में चूक होती है, या अकुशल लोगों को काम पर रखा जाता है। इसमें जब कोई गड़बड़ होती है तो उसमें सबसे पहले श्रमिक ही प्रभावित होता है। कभी दुर्घटना का शिकार होकर किसी का अंग-भंग होता है, या जान चली जाती है, तो कुछ लाख रूपए का मुआवजा देकर बात आयी-गयी की जाती है। जो इंसान आठ-दस घंटे श्रम करके भी एक लाख रुपए नहीं कर पाता, उसे या उसके परिवार को अगर एकमुश्त कई लाख रूपए मिल जाएं, तो फिर कौन नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। फिर पूंजीवादी व्यवस्था का जाल भी ऐसा है कि गरीब को इंसाफ मिलने की उम्मीद रंचमात्र भी नहीं रहती है। इसलिए श्रमिकों के हक में यदा-कदा आवाज उठने के बाद भी उनकी जीवनस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। बहरहाल, इस हादसे के बाद वेदांता कंपनी ने मृतकों के परिजनों के लिए 35 लाख रुपए मुआवजा और साथ ही रोजगार सहायता देने की घोषणा की है। वहीं घायलों के परिवारों के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार की तरफ से मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस हादसे पर दुख जताया है, साथ ही मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। चूंकि मृतकों में बंगाल से आए मजदूर भी शामिल हैं, शायद इस वजह से अभी प्रधानमंत्री को अचानक मजदूरों का दर्द दिखाई दिया है। इसके अलावा सक्ती कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि यह साफ हो सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। कंपनी ने भी अपने स्तर पर अंदरूनी जांच शुरू कर दी है। इस जांच में यह समझने की कोशिश की जाएगी कि हादसा तकनीकी गड़बड़ी से हुआ या फिर किसी की लापरवाही इसकी वजह बनी साथ ही प्लांट में सुरक्षा इंतजाम कितने मजबूत थे इसकी भी पड़ताल की जाएगी। जांच के ऐसे ऐलान सुनकर उम्मीद बंधती है कि वाकई दोषियों की शिनाख्त होगी, लेकिन सच यही है कि औद्योगिक हादसों के बाद किसी को सजा मिली हो, ऐसे प्रकरण बेहद कम हुए हैं। अक्सर पूंजीतंत्र प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था में अपने लिए बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ लेता है और भीतर बैठे लोग ही उसकी मदद करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए बहुत सारी खबरें आम जनता तक पहुंच जाती है। वर्ना सत्ता और शक्तिसंपन्न लोगों की कोशिश यही रहती है कि ऐसी खबरें दब जाएं, या प्रकाशित-प्रसारित हों भी तो उनमें पूरा सच बयां न हो। यही हाल जांच समितियों का भी किया जाता है जिनमें नाम के लिए कुछ सेवानिवृत्त लोगों को बिठा दिया जाता है, उसके बाद समय बिताने का सिलसिला शुरू होता है। वक्त बीतने के साथ हादसे की बात होनी कम हो जाती है और जांच कब ठंडे बस्ते में चली जाती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए वेदांता पावर प्लांट का हादसा भी कितने वक्त तक लोगों को याद रहता है।

मौसम विभाग की आंख मिचोली, कभी लू तो कभी बरसात

अब तक, ला नीना में नरमी आ गई है और स्थिति तटस्थ है, लेकिन आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि जून के बाद अल नीनो का प्रभाव बढ़ेगा, जो मानसून के लिए अनुकूल नहीं है। इसके संभावना बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इस साल की स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा 92 प्रतिशत बारिश का पूर्वानुमान पिछले तीन दशकों में सबसे कम है।

वर्तमान में, देश भर में मौसम में बड़ा बदलाव है, कुछ हिस्सों में गरज और गरज के साथ तूफान और कुछ हिस्सों में गर्मी की लहर और आर्द्र मौसम की चेतावनी दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 21 अप्रैल तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान के अनुसार, महाराष्ट्र सहित 13 राज्यों में लू चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 19 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा में 17 से 19 अप्रैल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और रायलसीमा में 17 और 18 अप्रैल को लू की स्थिति की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में पश्चिमी हवाओं के साथ एक पश्चिमी प्रणाली सक्रिय है। 16 अप्रैल की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया लेकिन कमजोर पश्चिमी सिस्टम आने की संभावना है। इसके कारण, उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। मध्य, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में गर्म हवा के साथ आर्द्र मौसम की संभावना है। 16 से 19 अप्रैल तक पूर्वोत्तर भारत के असम और मेघालय में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। गरज के साथ बारिश की संभावना है। 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। नागपुर जिला प्रशासन ने विदर्भ में लू की स्थिति और पारा 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहे मद्देनजर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हाई अलर्ट जारी किया है।अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अविनाश गवांडे ने कहा कि कोल्ड बाथ रखा गया है और पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।पुणे में आज और कल तापमान बढ़ेगा और 17 अप्रैल को पुणे में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि दोपहर में काम न होने पर बाहर न निकलें। पुणे में तापमान 42 डिग्री तक जाने की संभावना है। 18 और 19 अप्रैल को पुणेकरों को मिलेगी गर्मी से राहत शहर में कुछ बारिश होने की संभावना है। सड़कें सुनसान हैं। बताया जाता है कि पश्चिम एशिया में अभी भी युद्ध के बादल घने होने के साथ, इस साल का मानसून और भी शुष्क होने की उम्मीद है, दो गहराते बादलों के संयुक्त प्रभाव के साथः तेल की अनिश्चितता, आयात-निर्यात में देरी और युद्ध के कारण मुद्रास्फीति, बिना किसी वर्षा के। पीने के पानी का भी संकट है। कम से कम जल संकट के लिए तैयारी करना संभव है, इस तथ्य को देखते हुए कि युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। बेहतर होगा कि अगर हम अभी करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इससे समस्याएं ही पैदा होंगी। इस संभावित संकट पर ध्यान देना जरूरी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने हाल ही में इस साल देश में सामान्य से 92 प्रतिशत बारिश होने का दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी किया है। इसलिए तैयार रहना जरूरी है। ला नीना और अल नीनो दो कारक हैं जिनका हमारी वर्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो 'ला नीना' बारिश के लिए अच्छा है और 'अल नीनो' मारक है। अल नीनो की स्थिति के दौरान, अधिकांश समय वर्षा सामान्य से कम होती है। अब तक, ला नीना में नरमी आ गई है और स्थिति तटस्थ है, लेकिन आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि जून के बाद अल नीनो का प्रभाव बढ़ेगा, जो मानसून के लिए अनुकूल नहीं है। इसके संभावना बढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इस साल की स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा 92 प्रतिशत बारिश का पूर्वानुमान पिछले तीन दशकों में सबसे कम है। इस संबंध में और अधिक तैयारी करना आवश्यक है। पिछले तीन दशकों में बढ़ता शहरीकरण, इसकी बढ़ती आबादी और राज्य के किसी भी शहर में पीने के पानी की कमी से विकट स्थिति पैदा हो सकती है। पुणे, मुंबई और ठाणे जैसे शहरों में नवविकसित क्षेत्रों में बड़ी इमारतों को अभी भी पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पानी के वितरण में ढिलाई बरती जा रही है, लेकिन उन क्षेत्रों के लिए भी जहां पानी कम होने पर पाइप से पानी बहता है। इस तरह के संकट में मुनाफाखोरी कैसे हो सकती है और यह कैसे आम आदमी को बर्बाद कर सकती है, यह नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र के कई बांध सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन चूंकि पानी की कमी के समय पीने के पानी को प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए कम वर्षा के पूर्वानुमान का कृषि पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन में व्यवधान केवल समस्याओं को बढ़ाएगा। वर्तमान में महाराष्ट्र के बांधों में जल भंडारण पिछले साल की तुलना में अधिक है। इसकी योजना अभी तत्काल प्राथमिकता है। आईएमडी मई के अंत तक संशोधित मानसून पूर्वानुमान जारी करेगा। वर्तमान पूर्वानुमान में सबसे आश्वस्त करने वाली चीजों में से एक यह है कि मानसून के बाद की अवधि में हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) की स्थिति सकारात्मक होने की संभावना है। IOD हिंद महासागर की पूर्वी और पश्चिमी महासागर सतहों पर तापमान में अंतर है। जब पश्चिम में समुद्र की सतह का तापमान औसत से ऊपर होता है, तो आईओडी सकारात्मक होता है, जो अच्छी वर्षा के लिए उपयोगी होता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि बाद के वर्षों में यह प्रभाव कितना देखा जाएगा, और यदि यह वास्तव में सकारात्मक होने जा रहा है, तो मानसून के पहले चरण में क्या किया जाना चाहिए? इसका उचित कारण यह है कि हमारे शासकों में इस संभावित संकट से निपटने की इच्छाशक्ति नहीं है, शायद पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, नारी शक्ति वंदन आदि जैसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवधानों के कारण, लेकिन यह जलवायु संकट हमारे शासकों की प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए। स्थिति का उदाहरण याद रखें। दरअसल, बारिश के मौसम की तरह ही सर्दियों के आगमन को भी नेमेची कहा जाता है। हालांकि, नियमित बारिश के कारण, मुंबई में नियमित रूप से गड्ढे होते हैं और सामान्य ठेकेदारों को भीख मांगने का मौका मिलता है। साथ ही दिल्ली में सर्दियों में हवा प्रदूषित होती है और कई लोगों के पास छाती के पिंजरे होते हैं। लेकिन हमारे शासक प्रदूषण को रोकने के लिए निवारक उपाय नहीं करना चाहते हैं, कम से कम इसे कम करने के लिए। इसका कारण यह है कि यदि पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए जाते हैं, तो भी इसके परिणामों का अनुभव करने के लिए संबंधित लोगों को कुछ समय देना पड़ता है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय वृक्षारोपण के समान हैं। पेड़ लगाने वालों के लिए उस पेड़ के फलों का स्वाद लेना संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह हमें पेड़ लगाना बंद नहीं करना है, उसी तरह हमें पर्यावरण की रक्षा के उपाय करने से नहीं बचना चाहिए। इस संदर्भ में, यह सीखने लायक है कि चीन के बीजिंग, जिसे कभी दुनिया में सबसे प्रदूषित माना जाता था, ने पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम इस तरह सीखेंगे।

अशोक भाटिया

बेहतर तो यह होगा ...

कमलेश पांडेय

आखिर लोकसभा-विधानसभा जैसे निर्वाची निकायों में एससी-एसटी की तरह कब से लागू होगा ओबीसी-डब्ल्यूएस आरक्षण?

भारत में लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधानपरिषद के सदस्यों के लिए होने वाले चुनावों में अभी तक ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और गरीब सवर्णों (पददलित सामान्य जातियों) को दलित-आदिवासियों (एससी-एसटी) की तरह आरक्षण प्राप्त नहीं है! लिहाजा आगामी परिसीमन (जून 2026) में इस मुद्दे को भी शामिल किया जाना चाहिए। बताया गया है कि महिलाओं को मिलने वाला 33 प्रतिशत आरक्षण भी उनके कोटे के भीतर ही दिये जाने की योजना है। अपुष्ट खबर मिली है कि सरकारी रणनीतिकारों की योजना भी कुछ ऐसी ही है जिसमें राजनीतिक दबाव वश कुछ फेरबदल भी संभव है।पड़ने वाले बताया जाता है कि आगामी परिसीमन के बाद ओबीसी (OBC) और गरीब सवर्णों (EWS) के लिए यह लागू होगा। यहां पर एक अहम सवाल और है। वह यह कि दलितों के भीतर महादलितों और ओबीसी के भीतर ईबीसी/एमबीसी, और आदिवासियों के भीतर धर्मांतरित आदिवासियों सहित सबके लिए क्रीमीलेयर वाला प्रावधान भी अविलम्ब लागू किया जाए। बेहतर तो यह होगा कि इनकी जातीय रोटेशनल चार्ट घटती कुल आबादी के अनुरूप बनाकर आरक्षण की भावना को व्यवहारिक अमलीजामा पहनाएं।अन्यथा इनके भीतर भी कुछ ही लोगों को फायदा मिलेगा।यही वजह है कि आरक्षण का पवित्र मुद्दा अब राजनीतिक गोलबंदी में घिरकर हांफने लगा है। बता दें कि दलितों और आदिवासियों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद जैसे निर्वाची निकायों में लगभग 24 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। लेकिन ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और गरीब सामान्य जातियों (पददलित सवर्णों) के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित किये जाने हेतु लोगों की मांग विचाराधीन है और उम्मीद है कि आगामी परिसीमन आयोग (जून 2026) के गठन के बाद आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत लागू है। जबकि राज्यसभा और विधानपरिषद (जहां मौजूद हो) में भी राज्य-स्तरीय ओबीसी (OBC) सूचियों के आधार पर आरक्षण है, जो 2021 के 105वें संशोधन से राज्यों को सूची बनाने का अधिकार मिलने के बाद मजबूत हुआ। यह 1992 के इंदिरा साहनी मामले से 50% सीमा के भीतर है। वहीं, गरीब सवर्णों (EWS) के लिए 10% आरक्षण 2019 के 103वें संशोधन (अनुच्छेद 15(6) और 16(6)) से नौकरियों और शिक्षा में मिला, लेकिन विधायी निकायों में यह अभी लागू नहीं है। बताया जाता है कि परिसीमन आयोग (2026 तक) के बाद 2028-29 के लोकसभा/विधानसभा चुनावों से लागू होगा, क्योंकि संरक्षण अनुसूची में बदलाव जरूरी है। वहीं, राज्यसभा/विधानपरिषद में राज्य-विशेष नीति पर यह निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि आखिर में यह कब और कैसे लागू होगा? तो जवाब होगा कि परिसीमन 2026 तक पूरा होने पर OBC/EWS कोटे वाले सीटें तय होंगी, जो आम चुनाव 2029 और उसके बाद होने वाले अन्य विस चुनावों से प्रभावी होंगी। वहीं, राज्यसभा/विधान परिषद में राज्य विधायकों द्वारा नामांकन/चुनाव पर लागू होगा। चूंकि बिहार जैसे राज्यों में 50% से अधिक की मांगें लंबित हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होंगी। उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण को सीधे तौर पर नहीं बदलता, बल्कि यह लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का पुनर्वितरण करता है, जिसमें OBC के लिए 27% और EWS कोटा पहले से लागू है। जहां तक परिसीमन की समयरेखा की बात है तो परिसीमन आयोग जून 2026 तक गठित हो सकता है और 2011 जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाएगा। जैसे- SC/ST कोटे में वृद्धि जैसे 84 से 136 SC सीटें मिलेंगी। वहीं, OBC आरक्षण का निर्धारण राज्यवार 'ट्रिपल टेस्ट' (पिछड़ापन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की कमी, डेटा) से होता है, जो परिसीमन के बाद स्थानीय/राज्य आयोग तय करेंगे। इससे OBC आरक्षण पर प्रभाव पड़ेगा। 2029 के आम चुनावों से नए परिसीमन प्रभावी होंगे, लेकिन OBC कोटा वर्तमान 27% ही रहेगा जब तक संवैधानिक संशोधन या अदालती फैसला न हो। चूंकि पंचायत/स्थानीय निकायों में OBC आरक्षण परिसीमन से पहले डेडिकेटेड आयोग तय करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के 50% वाले कैप के अधीन रहेगा। वहीं, राज्यसभा/विधानपरिषद में OBC सूची पर निर्भर करेगा, और परिसीमन का सीधा असर नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि परिसीमन आयोग OBC कोटे को सीधे प्रतिशत (27%) के रूप में नहीं बदलता, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में कुल सीटों की संख्या बढ़ाने से OBC आरक्षित सीटों की कुल संख्या बढ़ सकती है। यही बात EWS कोटे पर भी लागू होती है, जिसके लिए 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। जहां तक परिसीमन का OBC व EWS पर पड़ने वाले प्रभाव की बात है तो परिसीमन मुख्यतः SC/ST के लिए आरक्षित सीटें जनसंख्या अनुपात (2011 जनगणना) से तय करता है, जबकि OBC कोटा राज्यवार 'ट्रिपल टेस्ट' (पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, डेटा) से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग निर्धारित करते हैं। ऐसे में यदि लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 850 हों, तो OBC की 27% सीटें अनुपातिक रूप से बढ़ेंगी (लगभग 146 से 230), लेकिन 50% कुल आरक्षण सीमा (SC/ST/OBC) का पालन जरूरी है। इसलिए EWS को अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य प्रावधानों के मुताबिक ही दिए जा सकते हैं।

संभावित मंदी...

नन्तू बनर्जी

बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं कीमतें और मुद्रास्फीति

रेपो दर में बढ़ोतरी से आमतौर पर गृह, व्यक्तिगत और व्यावसायिक कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जबकि रेपो दर में कमी होने पर ये ऋण सस्ते हो जाते हैं। केंद्रीय बैंक अक्सर मुद्रास्फीति के लिए एक आदर्श सीमा तय करते हैं—जैसे कि भारत के मामले में यह सीमा दो से छह प्रतिशत है—और वे इस आधार पर रेपो दर में बदलाव करते है। रस की खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और कमज़ोर भारतीय रुपये के कारण देश में सभी वस्तुओं और परिवहन की लागत में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की खुदरा कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। खाने के तेल, दालों और पैकेटबंद खाने की चीज़ों, जिनमें पीने का पानी भी शामिल है, की कीमतें पिछले महीने से बढ़ गई हैं। कीमती धातुओं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। 8 अप्रैल, 2026 को कुछ बाज़ारों में सोने की कीमतें 10 ग्राम पर 153,000 रुपये से ऊपर पहुंच गईं, जिसकी मुख्य वजह सोने में 'सुरक्षित निवेश की मांग थी। कोकिंग कोयले जैसे कच्चे माल की लागत में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर स्टील बनाने वालों पर पड़ा है, जिनमें से 95 प्रतिशत लोग आयात पर निर्भर हैं। खाने की चीज़ों की थोक महंगाई फरवरी से तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसमें तिलहन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। भारत की थोक कीमतें अकेले फरवरी में 2.13 प्रतिशत बढ़ीं - जो एक साल में सबसे तेज़ बढ़ोतरी थी- और इसकी मुख्य वजह मैन्युफैक्चरिंग और खाने की चीज़ों की ऊंची कीमतें थीं। विडंबना है कि देश का रिजर्व बैंक महंगाई के इस परेशान करने वाले रुझान को लेकर कम चिंतित लग रहा है, और उसका ज़्यादा ध्यान महंगाई के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखने पर है। पिछले हफ़्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार दूसरी बार रेपोरेट को 5.25 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया, जो एक लंबे ठहराव का संकेत है। रिजर्व बैंक का दरों को स्थिर रखने का फैसला, मज़बूत घरेलू विकास और बढ़ती महंगाई के दबाव के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत से प्रेरित माना जा रहा है। ऐसा लगता है कि इस $फैसले पर सरकारी नीति का काफ़ी असर पड़ा है। सरकार बढ़ती महंगाई, आयात की बढ़ती लागत, घटते निर्यात, घरेलू मुद्रा के गिरते मूल्य और पश्चिम एशिया से आने वाले पैसे (रेमिटेंस) में भारी गिरावट जैसी कई चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था के विकास को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि रिजर्व बैंक 2026 में एक सतर्क, 'तटस्थ मौद्रिक नीति बनाए रखेगा, और महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों को स्थिर रखेगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भू-राजनीतिक तनाव और तेल की बढ़ती कीमतों के कारण ज़रूरी हुई ऊंची दरें, भारत की जीडीपी वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7.6 प्रतिशत से घटाकर 2026-27 में 6.9 प्रतिशत या उससे भी कम कर सकती हैं।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

सौरभ वार्ष्णेय

सामाजिक कल्याण बनाम धार्मिक हस्तक्षेपः संतुलन की अनिवार्यता

अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से एक टिप्पणी की सामाजिक कल्याण के नाम पर किसी धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। किसी भी अदालत के लिए लाखों लोगों की आस्था को गलत ठहराना मुश्किल है। समाज के विकास और प्रगतिशीलता के नाम पर किए जाने वाले सुधारों का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होता है। लेकिन जब यही सुधार किसी धर्म की मूल संरचना, परंपराओं और आस्थाओं को प्रभावित करने लगते हैं, तब एक गंभीर प्रश्न खड़ा होता है—क्या सामाजिक कल्याण के नाम पर किसी धर्म को कमजोर या खोखला किया जा सकता है? अगर हम इस टिप्पणी को समझने की कोशिश करते हैं तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहां अनेक धर्म, परंपराएं और संस्कृतियां साथ-साथ विकसित हुई हैं, वहां यह सवाल और भी संवेदनशील हो जाता है। संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में सुधारों की प्रक्रिया को इस संवैधानिक संतुलन का सम्मान करना ही होगा। इतिहास गवाह है कि समाज में कई सुधार आवश्यक रहे हैं—चाहे वह सती प्रथा का उन्मूलन हो, बाल विवाह पर रोक हो या महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में उठाए गए कदम। इन सुधारों ने न केवल समाज को मानवीय बनाया, बल्कि धर्मों की आत्मा को भी शुद्ध किया। इसलिए यह कहना भी सही नहीं होगा कि हर सुधार धार्मिक हस्तक्षेप है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सुधार के नाम पर किसी विशेष धर्म या समुदाय को लक्षित किया जाता है, या उसकी आस्थाओं को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। यह न केवल सामाजिक विभाजन को बढ़ाता है, बल्कि सुधारों के उद्देश्य को भी संदिग्ध बना देता है। सुधार यदि समानता, न्याय और मानवाधिकार के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हों, तो वे स्वीकार्य होते हैं; लेकिन यदि उनमें राजनीतिक या वैचारिक पक्षपात झलकता है, तो वे विरोध को जन्म देते हैं। सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि वे सुधार और आस्था के बीच एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। सुधारों का लक्ष्य कुरीतियों को समाप्त करना होना चाहिए, न कि किसी धर्म की पहचान को कमजोर करना। साथ ही, धार्मिक समुदायों को भी आत्ममंथन के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि वे समय के साथ सकारात्मक बदलावों को स्वीकार कर सकें। यह समझना आवश्यक है कि सामाजिक कल्याण और धार्मिक स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं—बशर्ते दोनों के बीच संतुलन और संवेदनशीलता बनी रहे। सुधार तब ही सार्थक होंगे जब वे समाज को जोडने का काम करें, न कि उसे विभाजित करने का। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्य बागची जैसे न्यायमूर्ति अनुभवी हैं। इनकी अदालतों में कई ऐसे मामले आये होंगे। मामले की सुनवाई के दौरान 9 न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा अनु'छेद 25(2)(ख) और अनु'छेद 26(ख) के तहत किसी धार्मिक संस्था को अपने मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के बीच परस्पर संबंध पर दिए गए तर्कों को सुनते हुए यह टिप्पणी की। ज्ञात रहे कि अनु'छेद 25(2)(ख) राOय को सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बनाने या सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और समुदायों के लिए खोलने की अनुमति देता है। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की ओर से पेश होते हुए, सिंघवी ने तर्क दिया कि यद्यपि अनु'छेद 25(2)(ख) के तहत हिंदुओं के सभी संप्रदाय सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थान में प्रवेश की मांग कर सकते हैं, वहीं धार्मिक संप्रदाय को अनु'छेद 26(ख) के तहत आंतरिक अनुष्ठानों के संचालन को विनियमित करने का अधिकार होगा। उन्होंने अनु'छेद 25(2)(ख) और अनु'छेद 26(ख) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की वकालत की। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने भी इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सामाजिक सुधार का एक उदाहरण हो सकता है। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की, सामाजिक कल्याण और सुधार के नाम पर आप धर्म को खोखला नहीं कर सकते। केरल के सबरीमाला मंदिर को लेकर चला विवाद केवल एक धार्मिक परंपरा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान, लैंगिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन की एक जटिल परीक्षा बन चुका है। सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार, भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है। इसी आधार पर 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था। समर्थकों का तर्क है कि यह परंपरा धार्मिक आस्था से जुड़ी है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर, विरोधियों का कहना है कि यह प्रतिबंध महिलाओं के मौलिक अधिकारों—विशेषकर समानता और गरिमा—का उल्लंघन है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 2018 में आया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है और महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने चाहिए। फैसले के बाद केरल सहित देशभर में व्यापक विरोध-प्रदर्शन हुए। कई श्रद्धालुओं ने इसे आस्था पर आघात बताया, जबकि महिला अधिकार समूहों और प्रगतिशील वर्गों ने इसे एक बड़ी जीत के रूप में देखा। यह विवाद केवल धार्मिक नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन गया। फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को व्यापक संदर्भ में—अन्य धार्मिक प्रथाओं के साथ—बड़ी पीठ को सौंप दिया। फिलहाल कानूनी स्थिति जटिल बनी हुई है और अंतिम स्पष्टता का इंतजार है।

अगले हफ्ते धोनी आईपीएल में वापसी कर सकते हैं

वानखेड़े या चेपॉक में खेल सकते हैं, अभी काफ इंजरी से रिकवरी कर रहे हैं

नई दिल्ली, एजेंसी

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगले हफ्ते IPL में वापसी कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने टीम सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि उनकी चोट में तेजी से सुधार हो रहा है और वह आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। धोनी को IPL शुरू होने से करीब एक हफ्ते पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान पिंडली में खिंचाव आ गया था। इसी वजह से वह टूर्नामेंट के शुरुआती तीन हफ्तों में नहीं खेल पाए। अब उनकी वापसी को लेकर कयास तेज हो गए हैं। संभावना है कि धोनी 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मैदान पर उतर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह 26 अप्रैल को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ चेपॉक स्टेडियम में खेलते नजर आ सकते हैं। धोनी की वापसी केवल बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि विकेटकीपिंग

और रणनीतिक फैसलों के लिहाज से भी टीम के लिए बेहद अहम होगी। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने कई बार खिताब जीते हैं और मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देती है।फिलहाल टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस पर नजर बनाए हुए है और किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचना चाहता है। मेडिकल टीम की अंतिम मंजूरी के बाद ही धोनी को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा।धोनी के फैंस को अब बेसब्री से उनके मैदान पर उतरने का इंतजार है। अगर वह जल्द वापसी करते हैं, तो आईपीएल के इस सीजन में रोमांच और भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है।

प्रैक्टिस सेशन में की लंबी बल्लेबाजी, रेंज हिटिंग पर फोकस

भले ही धोनी मैच नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वे नेट प्रैक्टिस में लगातार पसीना बहा रहे हैं। धोनी ने हाल ही में नेट्स पर लंबी बल्लेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने अपनी 'रेंज हिटिंग'पर खास काम किया। नेट सेशन के दौरान धोनी पुराने अंदाज में लंबे छक्के लगाते दिखे, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि वे अपनी लय हासिल कर चुके हैं।

इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर हो सकता है इस्तेमाल

धोनी की वापसी के बाद CSK उन्हें किस भूमिका में रखेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। वर्तमान में संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और संभावना है कि वे ही इसे जारी रखेंगे।

ऐसे में टीम धोनी को 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। चेन्नई ने 5 में से 2 मैच जीते हैं इसलिए उन्हें पूरी तरह फिट होने का समय दिया जा रहा है।'

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे

चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से होना है। हालांकि, इस मैच में धोनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे। टीम मैनेजमेंट उनकी फिटनेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। CSK के सूत्रों ने कहा, 'धोनी अभी रिहैब प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हम उनकी फिटनेस के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहते।

चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 5 मैचों में से 2 में जीत दर्ज की है और वह अंक तालिका में फिलहाल 8वें स्थान पर है। धोनी की वापसी न केवल टीम के मध्यक्रम को मजबूती देगी, बल्कि उनकी रणनीतिक सूझबूझ से सीएसके को प्लेऑफ की दौड़ में वापस आने में मदद मिलेगी। इससे धोनी पर विकेटकीपिंग और दौड़ने का अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा और टीम उनकी पावर-हिटिंग का फायदा उठा सकेगी।

क्रिकेट कनाडा में करप्शन को लेकर आईसीसी की जांच

टी-20 वर्ल्डकप में न्यूजीलैंड और कनाडा का मैच भी शक के दायरे में

नई दिल्ली, एजेंसी

ICC की एंटी-करप्शन यूनिट (ACU) क्रिकेट कनाडा से जुड़े भ्रष्टाचार के दो मामलों की जांच कर रही है। इस जांच के दायरे में हाल ही में भारत और श्रीलंका में खेले गए टी-20 वर्ल्ड कप का एक मैच भी शामिल है। इसके अलावा, इंटरनेशनल और घरेलू लेवल पर एंटी-करप्शन कोड के संभावित उल्लंघनों की भी पड़ताल की जा रही है। ICC ने यह जांच कनाडा के पब्लिक ब्रॉडकास्टर CBC के कार्यक्रम में प्रसारित डॉक्यूमेंट्री 'करप्शन, क्राइम एंड क्रिकेट' में लगाए गए आरोपों के बाद शुरू की। 43 मिनट की इस फिल्म में कनाडा क्रिकेट के प्रशासन और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री में टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच का जिक्र किया गया है। मैच में कनाडा ने तेज गेंदबाजों से शुरुआत की थी, लेकिन तीसरे ओवर में ही स्पिनर साद बिन जफर को ले आए। इसके बाद अगले

स्पिनर के तौर पर रविंदरपाल सिंह बाजवा आए। बाजवा ने अपने ओवर की शुरुआत नो-बॉल से की, फिर लेग साइड पर एक वाइड फेंकी और अंत में उस ओवर में 15 रन दिए। बाजवा बल्लेबाज हैं जो पार्ट-टाइम ऑफ स्पिन करते हैं। उनके इसी ओवर की गेंदबाजी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह मैच भारत में 17 फरवरी को चेन्नई में खेला गया था। इस मैच में कनाडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। कनाडा ने 4 विकेट पर 173 रन बनाए थे। इस मैच को न्यूजीलैंड ने 28 गेंद शेष रहते हुए टारगेट हासिल कर लिया और मैच को 8 विकेट से जीत लिया था।

फास्ट न्यूज

दावा- विराट ने जर्मन मॉडल की फोटो लाइक की

मुंबई। क्रिकेटर विराट कोहली जर्मन मॉडल लिजलाज की एक फोटो को लाइक करने को लेकर चर्चा में आ गए। लिजलाज की फोटो क्लिक करने वाले फोटोग्राफर अद्वैत वैद्य ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया है कि विराट के आधिकारिक अकाउंट से लिजलाज की एक पुरानी फोटो को लाइक किया गया है। अद्वैत ने कैप्शन में लिखा, 'इस पर कैसे रिएक्ट करें जब GOAT विराट कोहली, आपकी पोस्ट लाइक कर दें।

विप्रो का मुनाफा सालाना आधार पर 1.89% घटा

मुंबई। आईटी कंपनी विप्रो ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4FY26) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। सालाना आधार (YoY) पर कंपनी का मुनाफा 1.87% गिरकर 3,502 करोड़ रुपए रहा है। पिछले साल इसी तिमाही में यह आंकड़ा 3,569 करोड़ रुपए था। हालांकि, पिछली तिमाही (दिसंबर) के मुकाबले मुनाफे में 12% से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिली है। पिछली यानी अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में मुनाफा 3,119 करोड़ रुपए था। विप्रो ने 16 अप्रैल को नतीजे जारी किए हैं। मार्च तिमाही में विप्रो का कुल रेवेन्यू 24,236 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही (22,504 करोड़ रुपए) के मुकाबले 7.69% ज्यादा है। पिछली तिमाही (दिसंबर) में कंपनी का रेवेन्यू 23,555.8 करोड़ रुपए था, जिससे इस बार 3% का सुधार हुआ है।

भूत बंगला में अक्षय के प्रैंक से कर्जदार बनीं वामिका-मिथिला

मुंबई। हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' की स्टार कास्ट में शामिल वामिका गब्बी और मिथिला पालकर ने से खास बातचीत में अपने शूटिंग अनुभव साझा किए हैं। दोनों ने बताया कि सेट पर जहां एक तरफ प्रोफेशनल डिसिप्लिन था, वहीं दूसरी तरफ मस्ती और हल्के-फुल्के माहौल की कोई कमी नहीं थी।

राम गोपाल ने धुरंधर 2 पर उठाया सवाल

कहा- फिल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल सही तरीके से नहीं दिखाया

मुंबई, एजेंसी

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 को लेकर कहा कि इसमें दाऊद इब्राहिम का किरदार सही तरीके से नहीं दिखाया गया। फिल्म धुरंधर 2 के रिलीज के बाद से ही राम गोपाल वर्मा इसकी क्राफ्ट और स्टोरीटेलिंग की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में राइटर हुसैन जैदी के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत में उन्होंने विस्तार से फिल्म को लेकर अपनी राय रखी। वर्मा ने कहा कि उन्हें फिल्म के कई पहलू प्रभावित करते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के किरदार को लेकर वह सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे बस एक बात से असहमति है। मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम को जिस तरह दिखाया गया है, वह सही नहीं है। उनके पास अपने सोर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में इसे

गलत तरीके से दिखाया गया है।' बता दें कि फिल्म में दाऊद को 'बड़े साहब' के रूप में दिखाया गया है, जो पाकिस्तान से भारत में आतंकी ऑपरेशन चलाने वाला मास्टरमाइंड है। वर्मा ने साफ किया कि वह इस विषय पर अंतिम अधिकार का दावा नहीं करते, लेकिन उनके अनुसार दाऊद लंबे समय से इनएक्टिव है। वर्मा ने कहा कि उनकी समझ के मुताबिक, दाऊद करीब 20 साल पहले आपराधिक गतिविधियों से दूर हो चुका है। उन्होंने यह भी माना कि इस मुद्दे पर पूरी सच्चाई कोई भी कन्फर्म नहीं कर सकता।

8 घंटे काम की मांग सही, वे अब मां हैं और उन्होंने इस मुकाम को कमाया है

दीपिका के सपोर्ट में आईं कंगना

मुंबई, एजेंसी

फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों (वर्किंग आवर्स) को लेकर चल रही बहस के बीच एक्ट्रेस कंगना रनोट ने दीपिका पादुकोण का समर्थन किया है। हाल ही में खबरें आई थीं कि दीपिका पादुकोण ने अपनी शर्तों और फिक्स्ड वर्किंग शेड्यूल के कारण कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए हैं। दीपिका की मांग है कि वे दिन में केवल 8 घंटे ही काम करेंगी। अब इस मामले पर कंगना ने दीपिका का पक्ष लेते हुए कहा है कि उनका कहना बिल्कुल सही है और उन्होंने यह मुकाम मेहनत से कमाया है। कंगना ने अपने और दीपिका के शुरुआती संघर्ष के दिनों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि करियर के शुरुआती दौर में वे दोनों ही सफलता के लिए काफी जुनूनी थीं। कंगना ने कहा, एक वक्त था जब हम 12 से 14 घंटे की शिफ्ट से कम पर राजी नहीं होते थे। दीपिका ने एक बार मुझसे इम्तियाज अली की फिल्म के दौरान कहा था।

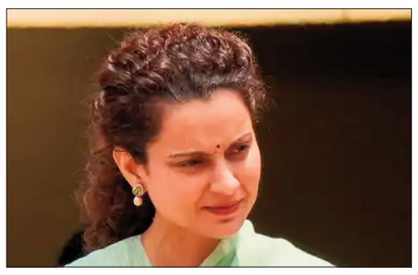

महिलाओं पर काम के दबाव पर जताई चिंता

वर्क-लाइफ बैलेंस पर बात करते हुए कंगना ने कहा कि आज के समय में महिलाओं पर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा, हम अपनी महिलाओं पर बच्चों के साथ-साथ दोगुना काम करने का बोझ डाल रहे हैं। फिर हम गिरती फर्टिलिटी रेट और टूटती शादियों की बात करते हैं। अगर दीपिका जैसी टॉप एक्ट्रेस अपने परिवार और काम के बीच तालमेल बिठाने के लिए समय मांग रही हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

संवाददाता को दिए एक इंटरव्यू में कंगना रनोट ने कहा कि समय के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कंगना ने कहा मुझे नहीं लगता कि इस बात पर कोई विवाद होना चाहिए। दीपिका आज जिस मुकाम पर हैं, वह उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। वे अब एक मां हैं, उनकी एक बेटी है। अगर आज वे 8 घंटे काम करना चाहती हैं, तो उन्होंने यह हक कमाया है। कंगना ने साफ किया कि जब कोई नया कलाकार होता है, तो उसे रिप्लेस (बदला) किया जा सकता है, लेकिन दीपिका जैसी स्टार के लिए मेकर्स को उनके समय के हिसाब से तालमेल बिठाना चाहिए।

नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जांच शुरू

7 पूर्व पीएम, 3 राष्ट्रपति, राजा की संपत्ति की जांच, 100 मंत्री अधिकारी भी दायरे में

काठमांडू, एजेंसी

नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने 5 सदस्यीय न्यायिक पैनल बनाया है, जो 2006 से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे लोगों की संपत्ति की जांच करेगा। जांच के दायरे में 2005-06 के बाद के सभी 7 प्रधानमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सुशील कोईराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा शामिल हैं। इसके साथ ही दो अंतरिम सरकारों के प्रमुख खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की भी जांच के दायरे में आएंगे। इसमें पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी आएंगे। इसके अलावा तीन राष्ट्रपति राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी और मौजूदा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी जांच के घेरे में होंगे। यह जांच सिर्फ बड़े नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे 100 से ज्यादा लोग और वरिष्ठ नौकरशाह भी शामिल होंगे।

मृत नेताओं की संपत्ति की भी जांच

यह जांच नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद के पूरे दौर को कवर करेगी। इसका मतलब 2006 के बाद का लगभग पूरा राजनीतिक नेतृत्व अब जांच के दायरे में आ गया है। खास बात यह है कि यह जांच शाह सरकार के अपने राजनीतिक दायरे तक भी जा सकती है। पोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा स्पीकर डोल प्रसाद अर्याल, मंत्री बिराजभक्त श्रेष्ठ और शिशिर खानाल, और अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख रवि लामिछाने भी जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि वे पहले भी सार्वजनिक पदों पर रह चुके हैं।

रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज करेंगे आयोग की अध्यक्षता

इस 5 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं। यह पैनल 5 मार्च के चुनाव के कुछ हफ्तों बाद बनाया गया है, जिसमें शाह की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। यह जीत पिछले साल हुए युवाओं के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद मिली थी। सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह सबूतों और कानून के आधार पर निष्पक्ष तरीके से होगी।

वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट डील घोटाला (2018): नेपाल एयरलाइंस द्वारा एयरबस विमान खरीद में अरबों रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगा। इसमें तत्कालीन पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों और एयरलाइंस प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठे।

भूकंप राहत घोटाला (2015): 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और पुनर्वास के लिए आए फंड और सामग्री के वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगे। स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक नेटवर्क पर मदद के दुरुपयोग के आरोप सामने आए।

सुदूर दूरसंचार/टेलीकॉम लाइसेंस घोटाला (2009): टेलीकॉम लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी और घूसखोरी के आरोप लगे। इसमें उच्च कंपनियों की मिलीभगत की बात सामने आई।

नेपाल में पूर्व राष्ट्रपति-PM की संपत्ति की जांच

पूर्व प्रधानमंत्री

यह मामला काठमांडू के बालुवाटार इलाके से जुड़ा है, जहां प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास भी है। यहां की जमीन पहले सरकारी और राजकीय (राणा काल की) संपत्ति मानी जाती थी, जिसे सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा गया था। कुछ नेताओं, अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर फर्जी कागज बनाकर इस जमीन को निजी लोगों के नाम कर दिया। धीरे-धीरे यह जमीन अलग-अलग लोगों को बेच दी गई और आखिर में कई प्रभावशाली लोगों के हाथ में पहुंच गई। सरकारी जमीन को पहले रिकॉर्ड में पुनर्वास के नाम पर दिखाया गया। फिर कागजों में बदलाव करके इसे निजी जमीन बना दिया गया। असली मालिकाना हक धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया और फर्जी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया।

पंजाबी महिला रेडियो होस्ट को कनाडा में सजा

मैसेज से खुलासा- गिरोह की मरोसेमंद पार्टनर थी

जालंधर, एजेंसी

कनाडा में रहने वाली पंजाबी रेडियो होस्ट को नशा तस्करी के केस में ब्रिटिश कोलंबिया की कोर्ट ने साढ़े 5 साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने 83 करोड़ रुपए की मेथामफेटामाइन ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। हालांकि कोर्ट में उन्होंने तस्करी में शामिल नहीं होने की दलील दी थी, लेकिन मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज से खुलासा हुआ कि वह न केवल इस तस्करी में अपनी मर्जी से शामिल थीं, बल्कि वह तस्करी गिरोह की एक भरोसेमंद पार्टनर थीं। नशा तस्करी केस में दोषी पाई गईं सुखविंदर कौर संघा (47) जालंधर के नकोदर से संबंध रखती हैं। हालांकि उनका जन्म कनाडा के प्रिंस जॉर्ज में हुआ था। उन्होंने पिछले एक दशक में पंजाबी रेडियो जगत में अपनी पहचान बनाई थी। वह फ्रीलांसर रेडियो और टीवी होस्ट थी। देखते ही देखते वह पंजाबी समुदाय का बड़ा चेहरा बन गईं। उनके शो में अक्सर हाई-प्रोफाइल राजनेता, पुलिस

अधिकारी और मशहूर हस्तियां शामिल होती थीं। मेथामफेटामाइन एक अत्यंत शक्तिशाली और नशीला सिंथेटिक उत्तेजक ड्रग है, जो सीधे शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर सफेद, गंधहीन और कड़वे स्वाद वाले पाउडर या कांच के टुकड़ों जैसे दिखने वाले 'क्रिस्टल' के रूप में पाया जाता है। इसके सेवन से मस्तिष्क में 'डोपामाइन' रसायन की भारी मात्रा निकलती है, जिससे व्यक्ति को अचानक ऊर्जा, अत्यधिक उत्साह और खुशी का अनुभव होता है।

तेजी : इस साल कीमत 21 हजार बढ़ी, सोना 241 महंगा होकर 1.53 लाख/10ग्राम हुआ

चांदी 2 हजार बढ़कर 2.51 लाख पर पहुंची

नई दिल्ली, एजेंसी

सोना-चांदी के दाम में आज यानी 16 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, एक किलो चांदी 2,273 रुपए बढ़कर 2.51 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले बुधवार को इसकी कीमत 2.49 लाख रुपए प्रति किलो थी। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 241 रुपए बढ़कर 153,106 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 15 अप्रैल को इसकी कीमत 1,52,865 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। बीते दो दिन में सोना 3,095 और चांदी 14,311 रुपए महंगी हुई है। सोना-चांदी में ये तेजी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फिर शुरू होने की उम्मीद बढ़ने से आई है। इससे कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, महंगाई का डर कम हुआ और डॉलर कमजोर पड़ा, जिससे निवेशक सोने-चांदी की तरफ लौटे हैं।

विदेशी जेवर मंगाने के लिए लाइसेंस लेना होगा

सरकार ने सोने-चांदी और प्लेटिनम के गहनों को 'फ्री' कैटेगरी से हटाकर 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया है। इसका सीधा असर बाजार की सप्लाई पर दिख रहा है, जिससे सोना-चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब इन कीमती धातुओं से बनी ज्वेलरी किसी भी देश से मंगाने के लिए सरकार से विशेष लाइसेंस या परमिशन लेना होगा। सरकार ने यह कदम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उठाया है।

असली चांदी की पहचान करने के 4 तरीके

- **मैग्नेट टेस्ट:** असली सिल्वर चुंबक से नहीं चिपकती। अगर चिपक जाए तो फेक है।
- **आइस टेस्ट:** सिल्वर पर बर्फ रखें। असली सिल्वर पर बर्फ तेजी से पिघलती है।
- **स्मेल टेस्ट:** असली सिल्वर में गंध नहीं होती। फेक में कॉपर जैसी गंध आती है।
- **क्लॉथ टेस्ट:** चांदी को सफेद कपड़े से रगड़ें। अगर काला निशान आए तो असली है।

ज्वेलर्स से सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान

1. सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है।

2. कीमत क्रॉस चेक करें: सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है।

सेंसेक्स 380 अंक चढ़कर 78,350 पर कारोबार कर रहा

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार, 17 अप्रैल को मजबूती देखने को मिली। BSE Sensex करीब 400 अंकों (0.49%) की तेजी के साथ 78,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं Nifty 50 भी 120 अंकों (0.51%) की बढ़त के साथ 24,300 के स्तर पर पहुंच गया है। आज के कारोबार में सेक्टरवार रुख मिला-जुला नजर आया। FMCG सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी दर्ज की गई, जिससे इस क्षेत्र के शेयरों में तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर आईटी सेक्टर दबाव में रहा और इसमें सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। विशेषज्ञों के अनुसार, बाजार में 'सपोर्ट' और 'रेजिस्टेंस' स्तरों की अहम भूमिका होती है। सपोर्ट वह स्तर होता है जहां किसी शेयर या इंडेक्स को गिरावट से सहारा मिलता है और यहां खरीदारी बढ़ जाती है। वहीं रेजिस्टेंस वह स्तर होता है जहां कीमतों को ऊपर जाने में बाधा आती है, क्योंकि यहां बिकवाली हावी रहती है। यदि कोई इंडेक्स रेजिस्टेंस स्तर को पार कर लेता है, तो आगे तेजी की संभावना बढ़ जाती है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर लिस्ट : अडाणी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने

नेटवर्थ 8.59 लाख करोड़, मुकेश अंबानी 8.42 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर

नई दिल्ली, एजेंसी

अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में उनकी नेटवर्थ 92.6 अरब डॉलर यानी करीब 8.59 लाख करोड़ रुपए हो गई है। अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनकी नेटवर्थ 90.8 अरब डॉलर यानी करीब 8.42 लाख करोड़ है गौतम अडाणी: इस साल इनकी नेटवर्त में 8.1 अरब डॉलर यानी 75.11 हजार करोड़ रुपए बढ़ी है।

अडाणी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी ने इनकी नेटवर्थ को बूस्ट दिया है। इनकी संपत्ति में इस साल 16.9 अरब डॉलर यानी 1.57 लाख करोड़ रुपए घटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट इसकी मुख्य वजह रही। एक

दिन में गौतम अडाणी की नेटवर्थ 3.56 अरब डॉलर यानी 33.01 हजार करोड़ रुपए बढ़ी है।

इसी उछाल ने उन्हें मुकेश अंबानी से आगे निकलने में मदद की। हालांकि, अंबानी की नेटवर्थ में भी 7.67 करोड़ डॉलर यानी 712 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह अडाणी की रफ्तार के सामने कम रही। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में इलॉन मस्क 656 अरब डॉलर यानी करीब 60 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं।

उनके बाद लैरी पेज दूसरे और जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर हैं। हालांकि कोई भी भारतीय टॉप टेन में शामिल नहीं है। यह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ को ट्रैक करने वाला एक डेली इंडेक्स है। इसमें न्यूयॉर्क में हर कारोबारी दिन की समाप्ति पर आंकड़े अपडेट किए जाते हैं।

नेटवर्थ की गणना कंपनियों के स्टॉक की कीमत और अन्य सार्वजनिक होल्डिंग्स के आधार पर की जाती है। चूंकि यह बाजार पर आधारित है, इसलिए शेयरों के दाम गिरते ही रैंकिंग में बदलाव आ जाता है।

लखनऊ में गिरफ्तार, बोला- शेयर मार्केट डाउन होने पर 6 लाख का कर्ज हो गया था

एटीएम तोड़ने वाला निकला कंपनी का टीम लीडर

तमसा संकेत, एजेंसी

सरोजनी नगर, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में एटीएम मशीन को तोड़कर कैश लूटने की कोशिश करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि एक निजी कंपनी के वेयरहाउस में टीम लीडर के पद पर कार्यरत है। पूछताछ में सामने आया कि आर्थिक तंगी और कर्ज के दबाव ने उसे इस वारदात को अंजाम देने के लिए मजबूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार युवक की पहचान उन्नाव जिले के अजगैन थाना क्षेत्र के शेरशाह गांव निवासी 21 वर्षीय गुलशन कुमार के रूप में हुई है। वह Zomato के वेयरहाउस में टीम लीडर के तौर पर काम करता था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह लंबे समय से शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रहा था, लेकिन हाल के दिनों में बाजार में लगातार गिरावट आने से उसे भारी नुकसान हुआ। इसी वजह से उस पर 6

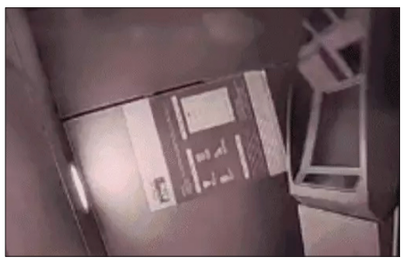

लाख रुपये से अधिक का कर्ज हो गया था। आर्थिक दबाव इतना बढ़ गया कि उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा और उसने एटीएम तोड़कर पैसे निकालने की योजना बना ली। आरोपी ने 11 अप्रैल की सुबह बंथरा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर स्थित हिताची एटीएम बूथ को निशाना बनाया। घटना के दौरान वह हेलमेट पहनकर बूथ के अंदर दाखिल हुआ, ताकि उसकी पहचान छिपी रहे। उसने अपने साथ लाए गए सब्बल से करीब 7 मिनट तक एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने मशीन को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भी कर दिया, लेकिन वह कैश निकालने में सफल नहीं हो सका। लगातार प्रयास के बावजूद जब उसे सफलता नहीं मिली, तो वह मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें आरोपी की गतिविधियां स्पष्ट रूप से कैद हो गई थीं। तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी शिक्षित और नौकरीपेशा युवक है, लेकिन गलत निवेश और कर्ज के बोझ ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया। यह मामला इस बात का भी संकेत देता है कि आर्थिक अस्थिरता और जल्द पैसे कमाने की चाह किस तरह युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा सकती है। फिलहाल पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस वारदात में आरोपी का कोई साथी भी शामिल था या उसने यह कोशिश अकेले ही की थी। साथ ही उसके बैंक खातों, निवेश और लेन-देन की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि पूरे मामले की गहराई से जांच हो सके।

लव मैरिज के बाद घरवालों ने अलग किया

गिरफ्तार आरोपी गुलशन ने बताया कि उसने 2024 में लव मैरिज की थी, जिससे नाराज होकर घरवालों ने उसे घर से अलग कर दिया था। इस समय वह बंथरा के ग्राम उम्मेदखेड़ा में किराये पर रहता है। बंथरा स्थित जोमैटो वेयरहाउस में टीम लीडर के रूप में काम करता है। पुलिस के अनुसार, आरोपी शेयर मार्केट और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के कारण करीब छह लाख रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब गया था। कर्ज चुकाने के दबाव में उसने एटीएम तोड़कर पैसे चोरी करने की योजना बनाई थी। वह तमाम कोशिशों के बावजूद एटीएम नहीं लूट सका।

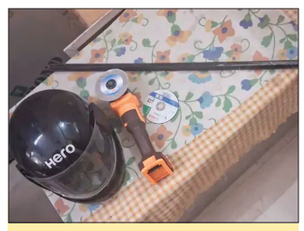

सब्बल, कटर, बाइक बरामद

पुलिस ने आरोपी कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया सब्बल, कटर और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बंथरा प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश सिंह ने बताया- 11 अप्रैल 2026 की सुबह बंथरा के पहाड़पुर स्थित हिताची एटीएम में एक अज्ञात व्यक्ति ने तोड़फोड़ कर कैश चोरी करने की कोशिश की थी। इस संबंध में हिताची की फ्रेंचाइजी लेकर एटीएम बूथ संचालित करने वाले पहाड़पुर निवासी शौर्य श्रीवास्तव ने बंथरा थाने में मामला दर्ज कराया था। एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए एक पुलिस टीम गठित की गई थी।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में किया जनता दर्शन

जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के दिए निर्देश

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री Keshav Prasad Maurya ने शुक्रवार को प्रयागराज स्थित सर्किट हाउस में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी विभिन्न शिकायतें और समस्याएं उप मुख्यमंत्री के सामने रखीं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही, जिन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उप मुख्यमंत्री ने एक-एक प्रार्थना पत्र को ध्यानपूर्वक देखते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता

को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार जनसेवा के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी के साथ कार्य करें और शासन की मंशा के अनुरूप हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है, ताकि आम नागरिकों का सरकार पर विश्वास और मजबूत हो सके।

फास्ट न्यूज

राहुल गांधी की नागरिकता विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

लखनऊ। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। यह मामला निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

एनकाउंटर में घायल बदमाश हैलट अस्पताल से भागा

कानपुर। कानपुर में पुलिस की गिरफ्त से एक शातिर बदमाश शुक्रवार सुबह अस्पताल से भाग गया। बर्रा में मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद उसे माइनर ऑपरेशन थियेटर में एडमिट कराया गया था। उसे तीन दरोगा और एक सिपाही की सुरक्षा में लाया गया था। एक गार्ड के मुताबिक, दो दरोगा हैलट के बाहर बनी चौकी में चले गए। एक दरोगा बाहर खड़ा था, एक सिपाही ऑपरेशन थियेटर के पास था। इसी बीच आरोपी माइनर ऑपरेशन थियेटर से निकला और भाग गया। ये वही आरोपी है, जिसने 24 घंटे पहले हाईवे पर तमंचे के दम पर युवक से मोबाइल और बाइक लूटी थी। फरार बदमाश जूही परमपुरवा निवासी मुन्ना है। पुलिस उपायुक्त क्राइम श्रवण कुमार सिंह ने कहा- तड़के आरोपी को अस्पताल लाया गया था। शुक्रवार सुबह 10 बजे आरोपी भागा।

मैं जिंदा लाश बन गई हूं...बोलकर छात्रा ने जान दी

कानपुर। कानपुर में CBSE 10वीं की छात्रा ने रिजल्ट आने के 24 घंटे बाद सुसाइड कर लिया। मां ने उसे कई बार फोन किया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। इस पर भाई उसके कमरे में पहुंचा तो बहन को फंदे से लटकता देखा। घटना गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे की है।
बुधवार शाम करीब 4 बजे उसने अपना रिजल्ट देखा था। सुसाइड करने से पहले छात्रा ने अपने साथियों को वॉयस रिकॉर्डिंग भेजी, जिसमें उसने कहा कि मेरे से जिया नहीं जाएगा।

'शंकराचार्य सपा के इशारे पर काम कर रहे हैं'

मंत्री बोले- अब गाय कसाई को देखकर नहीं कांपती, लखनऊ में 2 दिवसीय दुग्ध महोत्सव शुरू

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। गोमाता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और सरकार के प्रयासों के बारे में मैं कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गो संरक्षण के लिए दी जाने वाली दैनिक राशि को 30 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित दुग्ध स्वर्ण महोत्सव-2026 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय महोत्सव इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में हो रहा है। इसमें दुग्ध उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। धर्मपाल सिंह ने कहा- वर्तमान में हमारे पास 7,500 गो संरक्षण केंद्र हैं, जहां लगभग 13.5 लाख गायों का पालन-पोषण किया जा रहा है। इन पर प्रतिदिन 8 करोड़ से अधिक का खर्च आता है। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। मैं उद्यमियों और सक्षम नागरिकों से अपील करता हूं कि वे किसी

भी एक गोशाला (200-300 गायों वाली) को एक वर्ष के लिए गोद लें। धर्मपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 7,500 गो संरक्षण केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें लगभग 13.5 लाख गायों का पालन-पोषण किया जा रहा है। इन केंद्रों पर प्रतिदिन 8 करोड़ से अधिक खर्च किया जा रहा है।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अकेले इस व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावी ढंग से नहीं चला सकती, इसलिए समाज की भागीदारी बेहद जरूरी है। मंत्री ने उद्यमियों और सक्षम नागरिकों से अपील की कि वे 200 से 300 गायों वाली किसी एक गोशाला को एक वर्ष के लिए गोद लें और गो संरक्षण में अपना योगदान दें।कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों, उद्यमियों और किसानों की भागीदारी देखी गई। महोत्सव के माध्यम से डेयरी सेक्टर में नवाचार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

कसाई कानून को देखकर कांपता है

धर्मपाल सिंह ने कहा कि शास्त्र कहते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। मूत्र में गंगा मैया बसती हैं और इसका दूध अमृत के समान है। विशेष रूप से साहीवाल जैसी देसी नस्लों का दूध सर्वोत्तम माना जाता है। पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार में यही अंतर है कि पहले पशु चोरी के डर से किसान परेशान रहता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अब गाय कसाई को देखकर नहीं कांपती, बल्कि कसाई कानून को देखकर कांपता है। हमारा लक्ष्य है कि निराश्रित गोवंश सड़कों या खेतों में न दिखे, बल्कि उन्हें उचित संरक्षण और प्रेम मिले। आप सभी इस पुनीत कार्य में सहयोग दें।

अधिकारी और विशेषज्ञ भी रहे मौजूद

महोत्सव में अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम और दुग्ध आयुक्त धनलक्ष्मी के. समेत कई अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। यहां विभाग की योजनाओं और आगे की दिशा पर बातचीत हुई।महोत्सव में दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़ी नई तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई है। किसान और डेयरी से जुड़े लोग यहां आधुनिक तरीकों के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उन्हें अपनाने पर चर्चा कर रहे हैं। इस आयोजन में बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। करीब 10 हजार से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 50 से अधिक प्रदर्शक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 15 से ज्यादा चर्चा सत्र भी रखे गए हैं।

नोएडा में श्रमिकों से मिलने जा रहा सपा प्रतिनिधिमंडल रोका गया

रास्ते में रोके जाने पर सपा ने बताया लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन

तमसा संकेत, संवाददाता

नोएडा/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर श्रमिकों से मुलाकात के लिए नोएडा जा रहा पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस द्वारा बीच रास्ते में रोक दिया गया। यह प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में रवाना हुआ था। प्रतिनिधिमंडल में कमाल अख्तर, सुधीर भाटी, आश्रय गुप्ता, शाहिद मंजूर, अतुल प्रधान, पंकज कुमार मलिक, प्रशांत यादव, राज कुमार भाटी और सुनील चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। सभी नेता नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में पीड़ित श्रमिकों की समस्याएं जानने के लिए जा रहे थे। सपा नेताओं के मुताबिक, प्रस्थान से पहले पुलिस प्रशासन ने उन्हें उनके आवास पर ही नजरबंद करने का प्रयास किया,

लेकिन नेता निर्धारित कार्यक्रम के तहत बाहर निकलने में सफल रहे। इसके बाद रास्ते में पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को रोककर आगे बढ़ने से मना कर दिया। पार्टी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि नोएडा क्षेत्र में श्रमिकों से 10 से 12 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें केवल 10 से 11 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। साथ ही साप्ताहिक अवकाश तक नहीं दिया जा रहा। बताया गया कि Motherson India Limited, नोएडा फेस-2 के कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि और ओवरटाइम भुगतान की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था। आरोप है कि प्रशासन ने इस आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया और श्रमिकों के साथ अभद्र व्यवहार तथा लाठीचार्ज की घटनाएं भी सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी ने पुलिस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा है कि यह न सिर्फ जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है, बल्कि श्रमिकों की आवाज को दबाने का प्रयास भी है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह श्रमिकों के हक, सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखेगी और इस तरह की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाती रहेगी।

गैरहाजिर चल रहे 12 पुलिसकर्मी सस्पेंड

बगैर सूचना दिए एक महीने से लापता

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने बगैर बताए ड्यूटी से गायब चल रहे 12 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। नोटिस देने के बाद भी यह पुलिस कर्मी ऑफिस नहीं पहुंचे और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेते हुए यह कार्रवाई की है। अगर इसके बाद भी इन पुलिस कर्मियों का कोई जवाब नहीं मिला तो इनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि कई पुलिस कर्मी एक महीने से ज्यादा अवधि से बगैर बताए अपनी ड्यूटी से लापता है। इन पुलिस कर्मियों का हाल जानने के लिए आखिर क्यों लापता हैं...? ड्यूटी पर कब से आएंगे...? सभी को पत्र लिखकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बाद भी इन

पुलिस कर्मियों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह के 12 पुलिस कर्मियों को सूचीबद्ध करके उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। अगर अब इसके बाद भी एक सप्ताह के भीतर इन लापता पुलिस कर्मियों ने अपना स्पष्टीकरण नहीं तो तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इन सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ गोपनीय जांच भी कराई जा रही है कि आखिर ये पुलिस वाले क्यूं लापता हैं। इसके पीछे की वजह क्या है।

ग्रेटर नोएडा में सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट किया

गौतम बुद्ध नगर। ग्रेटर नोएडा में छह से अधिक समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये नेता आज नोएडा में प्रदर्शनकारी श्रमिकों से मुलाकात करने वाले थे। सपा नेताओं ने भाजपा सरकार पर मजदूरों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे प्रतिनिधि मंडल के साथ में श्रमिकों से मिलने जा रहे थे। लेकिन उन्हें नोएडा पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। उन्होंने कहा- ₹मैं इस प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां आया था। यहां लाठीचार्ज हुआ। मजदूरों के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिल रही थी। मैंने सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया भी था, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां के श्रम आयुक्त और श्रम निरीक्षक को मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था और उनका समाधान करना चाहिए था। यह सरकार सो रही थी। जब स्थिति और बिगड़ गई, तो उन्होंने लाठीचार्ज का सहारा लिया। दरअसल, नोएडा में श्रमिक अपनी वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

घटना : बहू ने मंदिर में दीया जलाया तो आग भड़की, धमाका सुन चौकी से भागे पुलिसकर्मी

गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से छत उड़ी

- गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद कमरे की सीमेंट शेड वाली छत उड़ गई।
- घटना की सूचना पर फायर बिग्रेड की एक टीम मौके पर पहुंच गई।
- आग लगने के बाद कमरे में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।

तमसा संकेत, एजेंसी

झांसी। झांसी में गुरुवार रात एक मकान में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इससे कमरे की छत उड़ गई और कॉलोनी में दहशत का माहौल हो गया। धमाका सुनकर पड़ोस में बनी चौकी के पुलिसकर्मी बाहर निकल आए। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। पुलिस

के फोन करने पर फायर बिग्रेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि महिला ने मंदिर में दीपक जलाया गया। इसके बाद ही आग भड़क गई। इससे फ्रिज, वाशिंग मशीन मशीन, दो मोबाइल, पैसे समेत एक लाख रुपए का सामान जल गया। घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नैनागढ़ चौकी के पास की है। दूसरे कमरे में आग पहुंचती, उससे पहले ही फायर बिग्रेड की एक गाड़ी आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग से दो फोन, पैसा, फ्रिज, वॉसिंग मशीन सबकुछ जल गया। लगभग एक लाख रुपए का सामान जल गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।

घरवालों को भी पता नहीं था आग लग गई

नैनागढ़ चौकी के पास रहने वाले जगदीश सिंह ने बताया- मैं ऑटो चलाता हूं। घर में किराना की दुकान है। गुरुवार रात को ऑटो चलाकर आया तो दुकान पर बैठा था। रात लगभग 8 बजे बहू ने छत पर बने कमरे में मंदिर के अंदर दीपक जलाया। इसके बाद वो नीचे आ गई। कुछ देर बाद कमरा में आग लग गई। यहां दो गैस सिलेंडर रखे थे। इसमें एक सिलेंडर भरा था। आग की वजह से भरा हुआ सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इससे कमरे की सीमेंट शेड वाली छत उड़ गई। क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।

जगदीश सिंह ने आगे बताया- धमाका सुनकर घर के बाहर निकला तो देखा कि ऊपर वाले कमरे में आग लगी थी। मैंने कमरे में जाने की कोशिश की, लेकिन लगातार निकल रही थी। आग इतनी तेज थी कि सीढ़ियों पर भी नहीं चढ़ पा रहा था।

पृष्ठ 01 का शेष...

महिला आरक्षण से ...

ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को दिया। शाह ने कहा- मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो बिल गिर जाएगा। मगर इस देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है। यहां पर तो शोर शराबा करके बच जाओगे लेकिन माताओं - बहनों का आक्रोश बाहर पता चलेगा। जब चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। वेणुगोपाल ने दो सवाल किए- एक तो 50 प्रतिशत सीटें बढ़ाने कि लए ऑफिशियल अमेंडमेंट लाने के लिए तैयार हैं। अमित शाहः हां मैं तैयार हूं, एक घंटे सदन बंद कर दीजिए। मैं अमेंडमेंट ला दूंगा। बोलिए तैयार हैं। परिसीमन 2026 की जनगणना का सवाल है तो मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। शाह ने कहा- जाति जनगणना का रिपोर्ट भी जाति के साथ ही जाएगा। उस पर सदन विचार करेगा और जो सामूहिक विचार बनेगा भाजपा उसके साथ आगे बढ़ेगी। उनके लिए चुनाव जीतना सर्वोपरि है। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। जनता जर्वोपरि है। कांग्रेस के मित्रों को कहता हूं कि सिर्फ नारे लगाने से देश का पिछड़ा वर्ग आपको हितैषी नहीं मानेगा। ये दिखावटी प्रेम देश की जनता जानती है। आज से देश की महिला भी जानेगी कि कांग्रेस ने हमारा अधिकार छीना। शाह ने कहा- नेहरू, इंदिरा और राजीव ने जीवन का सबसे लंबा भाषण मंडल आयोग का विरोध करने में दिया। क्योंकि अब मेल नहीं खा रहा है। 15-20 बार चुनाव हार गए तो ओबीसी का हीतैशी बन रहे हैं। अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को पीएम बनाया। किसी ओबीसी को पीएम नहीं बनाया। मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, 40 फीसदी हैं। मोदी सरकार ने ओबीसी कमीशन को मान्यता दी। ओबीसी की सूचियों को संशोधित करने का अधिकार राज्यों को दिया। शाह ने कहा- मैं सरकार की, संविधान की और भाजपा की पॉलिसी साफ करना चाहता हूं। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता। संविधान में कहीं पर भी धर्म के आधार पर आरक्षण की मान्यता नहीं है। इंडी अलायंस ने तुष्टीकरण के कारण मुस्लिम आरक्षण की मांग खड़ी करना चाहते हैं। हमारी सरकार की नीति साफ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण न आज देंगे न किसी को देने देंगे। ओबीसी आरक्षण पर- देश में ओबीसी का सबसे बड़ा कोई विरोध पार्टी है तो कांग्रेस है। इन्होंने चौधरी चरण सिंह और सीताराम केसरी, दोनों को कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया। 1957 में काकासाहेब समिति के सुझाव आए, कांग्रेस ने सुझाव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंदिरा सरकार में मंडल आयोग के सुझान को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

यूपी पुलिस का ...

जो जांच की गुणवत्ता को नए स्तर पर ले जाएगी। संस्थान के संस्थापक निदेशक डॉ. जी.के. गोस्वामी के अनुसार अब तक तीन बैचों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अमित शाह ने कहा कि सबने बोला है कि हम इसके पक्ष में है। हम स्वागत करते हैं मगर उसको बारिकी से देखें तो इंडी अलायंस के सभी सदस्यों ने अगर, मगर, किंतु, परंतु, का उपयोग करते साफ रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है। लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि ये विरोध केवल महिला आरक्षण का है। इम्पलीमेंटेशन का नहीं है। मैं जब बोलता हूं तब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सदन को कन्वींस करूं कि महिला आरक्षण का विरोध है। तरीकों का विरोध नहीं है। संसद में राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री और LJP सांसद चिराग पासवान ने कहा, आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को कम किया है। जब आप उदाहरण देते हैं और उन्हें PM से जोड़ते हैं तो आप अपनी सीमा पार कर जाते हैं। आप अपनी पार्टी के पहली बार सांसद बने सदस्यों के लिए किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं? कहीं न कहीं, उन्होंने अपने ही सांसदों के सामने खुद को हंसी का पात्र बना लिया है। इन 3 बिलों में इसका मकसद मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।चौथे बैच की शुरुआत 27 अप्रैल से होगी, जिसके बाद पांचवें चरण में भी विशेषज्ञ तैयार किए जाएंगे। सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ राज्य को अपराध नियंत्रण के मामले में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

राहुल के खिलाफ ...

याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता से जुड़ा गंभीर विषय है। शुक्रवार को सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से वकील डॉ. बीके सिंह पेश हुए थे। जबकि केंद्र सरकार का पक्ष वकील एसबी पांडेय ने रखा। याचिकाकर्ता विग्नेश पांडेय की तरफ से बिंदेश्वरी पांडेय कोर्ट में पहुंचे थे। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2025 को इस मामले को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद लखनऊ में MP/MLA कोर्ट ने 28 जनवरी, 2026 को याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने अब FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। याचिका में राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिए जाने की भी मांग की गई थी।

बुलंदशहर में सीओ से धक्का-मुक्की, झड़प

किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की

तमसा संकेत, एजेंसी

बुलंदशहर। बुलंदशहर-अलीगढ़ हाईवे पर स्थित गभाना टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इस दौरान किसानों ने शिकारपुर सीओ के साथ धक्का-मुक्की हुई। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। भारतीय किसान यूनियन (भानू) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गभाना टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। बुलन्दशहर-अलीगढ़ हाइवे पर 5 किमी लंबा जाम लग गया है। संगठन के कार्यकर्ता हापुड़ स्थित मुख्य कार्यालय जाने की तैयारी में हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक पूर्व मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर किसानों में आक्रोश है। सैकड़ों की संख्या में किसान टोल पर डटे हुए हैं, जिससे

अलीगढ़ से बुलंदशहर की ओर जाने वाली हाईवे पट्टी पर लंबा जाम लग गया है। मौके पर जिले के सभी सीओ और इंस्पेक्टर भारी पुलिस बल के साथ तैनात हैं। प्रशासन लगातार किसानों को समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रदर्शन जारी है। दरअसल, यह पूरा विवाद भाकियू भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री मदन चौहान के बीच हुई नोकझोंक से जुड़ा बताया जा रहा है।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकिशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676